SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: The bonemeal contains phosphate and super phosphate is available much cheaper and in abundant quantity. There is no shortage of super phosphate in the country. Therefore, I do not think any additional steps are required.

MR. SPEAKER: Next Question.

SHRI BIBHUTI MISHRA: Q. 1447.

SHRI SHER SINGH *rose*—

AN HON. MEMBER: This relates to labour. How is the Ministry of Agriculture concerned with it?

MR. SPEAKER: It was transferred to this Ministry.

फसलों के बीच के बेकारी के समय में खेतिहर मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था

*1447. **श्री विभूति मिश्र**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फसलों के बीच के बेकारी के समय में खेतिहर मजदूरों को रोजगार देने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHER SINGH): (a) and (b). The Crash Scheme for Rural Employment with an outlay of Rs. 50 crores during the year 1971-72 has been introduced with effect from April 1, 1971. The Scheme is implemented through the State Governments/Union Territories with 100% financial assistance by the Central Government. Additional employment is designed to be generated through a net work of rural projects of various kinds which are labour intensive and which will create durable assets. Employment is to be provided in every district for atleast 1,000 persons for a period of 10 months in a year at a wage not exceeding Rs. 100 per month. An amount equivalent to $\frac{1}{4}$ the of the wage cost will be available for materials and equipment. The order of outlay is Rs. 12.50 lakhs per district per annum.

श्री विभूति मिश्र: अध्यक्ष महोदय, यह तो पहले ही से हम लोगों को मालूम था लेकिन सवाल यह है कि 1 हजार आदमियों को एक जिले में यह काम देंगे और एक असेम्बली कांस्टीट्यूएंसी की आबादी है सवा लाख, अब उसमें आप गांव के रहने वाले हैं, आप खुद जानते हैं, उस सवा लाख आदमियों में कितने बेकार मिलेंगे और एक हजार आदमियों को एक जिले में यह क्या एम्प्लायमेंट देंगे ? उसमें भी कहते हैं कि 25 परसेंट तो मेटीरियल में चला जायगा और 75 परसेंट उस आदमी को मिलेगा ।.... (व्यवधान) ....तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कृषि के जरिए इस देश में जो गांवों के अन्दर बेकारी है उस को दूर करना चाहती है या कोई दूसरी स्कीम वह सोच रही है जिससे लार्ज स्केल पर बेकारी दूर हो ?

श्री शेर सिंह: माननीय सदस्य का विचार है 25 परसेन्ट इसमें मेटीरियल एक्विपमेंट पर लगेगा तो वह तो असल में कोई भी काम हम करें जिसमें ड्यूरेबल असेट्स बनाने हों, सड़कें बनानी हों, सायल कंजर्वेशन का काम करना हो, एफोरेस्टेशन का काम करना हो, माइनर इरीगेशन हो, सब के लिए मेटीरियल एक्विमेंट चाहिए । इसलिए 25 परसेन्ट अर्थात ढाई लाख उसके लिए रखा है और बाकी दस लाख वेजेज के लिए । यह एक प्रोग्राम है जिसमें अनस्किल्ड लेबर जो देहात में बहुत है और अंडर एम्प्लायड लोग हैं आफ सीजन में देहातों में उन को रोजगार मिल सके । यह ठीक है कि बहुत सी जगह एक हजार से ज्यादा आदमी बेरोजगार होंगे । सब को एकदम रोजगार मिल जाये इस योजना से यह संभव नहीं है । लेकिन यह जरूर इससे संभव होगा कि ऐसे इलाके जहां पर लोग बेरोजगार हैं और साल में ज्यादा दिनों तक बेरोजगार रहते हैं उनको कुछ काम मिले । और उस काम के द्वारा कुछ एसेट्स भी क्रिकेट हों ।

श्री विभूति मिश्र: अध्यक्ष महोदय, सवाल कुछ और जवाब कुछ और है । वर्षा काल में चार पांच महीने आम तौर से लोग बेकार रहते

हैं, तो मिट्टी का काम बरसात के दिनों में कैसे होगा। इसका जवाब पहले दे दें फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा।

श्री शेर सिंह: आपने यह सवाल अब किया है। यह ठीक है कि बरसात के दिनों में बेरोजगारी होती है, लेकिन कई बार नहीं भी होती है। आदमी अवेलेबल नहीं होते हैं। इसमें दस महीने हमने साल में रखा है। हो सकता है कि दस महीने कहीं काम न हो। इस योजना में हमारा विचार है कि 3 लाख के करीब मेन डेज पूरे होने चाहिए। तो उसमें चाहे कम महीने भी काम करें ज्यादा आदमी लगा सकते हैं। कोई एक हजार की ही बात नहीं है। मेन-डेज 3 लाख पूरे होने चाहिए। इसमें काफी लचक है इस योजना में।

श्री विभूति मिश्र: गांधीजी की योजना गांवों की बेकारी को दूर करने के लिए चरखा और काटेज इंडस्ट्रीज की थी। आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हमारी पार्टी के भी बहुत से लोग हैं जो खद्दर नहीं पहनते हैं और विरोधी पार्टी में तो खद्दर नहीं ही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि गांवों की बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार कौन-सी योजना बना रही है? क्योंकि इस लचक वाली योजना से काम नहीं चलेगा। अब कोई बेलचक वाली योजना आप बनाइए ताकि उस बेलचक वाली योजना से गांवों की बेकारी दूर हो और नक्सलाइट मूवमेंट कमजोर पड़े। मैं फखरुद्दीन साहब से जानना चाहता हूं, वह पुराने गांधीवादी हैं, गांवों की बेकारी दूर करने के लिए वह क्या कर रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): जो आनरेबल मेम्बर ने कहा जरूर तश्वीश की बात है लेकिन मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जो हमने अभी इस स्कीम को लिया है इससे सारी बेकारी तो दूर नहीं होगी। एक पाइलट प्रोजेक्ट की हैसियत से इस स्कीम को लिया गया है और एक साल में देखते हैं कि किस तरह से इसके जरिए से काम होता है। फिर आइन्दा साल इसको और बढ़ाने की कोशिश की जायेगी और बढ़ा कर के किस तरह से रूरल बेकारी दूर हो उसके लिए कोशिश की जायेगी।

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: As the hon. Minister has said that the aim of the programme is to have an impact on unemployment, may I know if he has tried to ascertain districtwise as to what is the percentage of employed and unemployed among those who are registered witn the employment exchanges? If so, how many per thousand persons in the district will be unemployed persons? What will be the percentage, will it be 0.002 per cent or 2 per cent, or what figure will it be?

SHRI SHER SINGH: Not all get registered in district exchanges. Of course, there are educated people who want employment get themselves registered in Employment Exchanges, but there are unemployed people also who never get themselves registered, but this is meant primarily for this type of unskilled labour who are out of employment for many months in the year in off-season days and we want to provide employment to them and thereby create some permanent assets as infra-structure so that it might generate some employment in future.

डा० गोविंददास रिछारिया: अभी मंत्री जी ने बताया था कि साढ़े बारह लाख रुपये उन्होंने प्रत्येक जिले का दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वितरण से बिहार और उत्तरप्रदेश के जिलों के साथ घनघोर पक्षपात हो गया है क्योंकि वहां आबादी बहुत घनी है और बेकारी तो आबादी के लिहाज से होती है तो क्या आप इसमें आगे सुधार करना चाहते हैं ताकि यह पक्षपात दूर हो?

श्री शेर सिंह: माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि बिहार वगैरह में साढ़े बारह लाख रुपये एक जिले को देने से बहुत कम मिलता है। बिहार में बहुत बड़े-बड़े जिले हैं। पूरे प्रदेश में कुल 17 जिले हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इसी तरह से और कुछ प्रदेश भी हैं। तो उन प्रदेशों के लिए हमने साढ़े बारह लाख रुपये के अतिरिक्त और भी रुपया दिया है। माननीय

सदस्य की सूचना के लिए जो ऐडीशनल एलोकेशन हमने किया है वह मैं पढ़ देता हूं :

आन्ध्र-प्रदेश–56.50 लाख, बिहार–245.50 लाख, केरल–34 लाख, उड़ीसा–20 लाख 50 हजार, तामिलनाडु 1 करोड़ 3 लाख, उत्तरप्रदेश 2 करोड़ 4 लाख, और वेस्ट बंगाल–99 लाख। तो इस तरह सात प्रदेशों को जहां जनसंख्या ज्यादा है यह ऐडीशनल एलोकेशन हमने किया है। . . . (व्यवधान) . . . मध्यप्रदेश में 43 जिले हैं पहले ही जिलों की संख्या वहां बहुत ज्यादा है। इसलिए अपने हिस्से से ज्यादा पहले ही मिल गया मध्यप्रदेश को।

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय मन्त्रीजी ने प्रश्न के उत्तर में बताया कि 1 हजार लोगों को साल भर में वह एक जिले में काम देंगे। तो क्या उन्होंने इस योजना को बनाते समय यह ध्यान दिया था कि एक जिले में बच्चों की पैदावार कितनी है और यह आगे जा कर कितना बैठेगा ? इस संबंध में आपने जो योजना बनाई है उसमें यह देखा है कि गांवों के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है और वह बेकार हैं, दूसरों के यहां काम करते हैं ? उनके लिए भूमी जो बेकार पड़ी है उसे खेती करने लायक बनाने की कोई योजना आपने बनाई है ? और बहुत से गांवों में अभी सड़कें पहुंचानी हैं, बिजली पहुंचानी है, तो सड़कों के निर्माण के लिए और बिजली पहुंचाने के लिए ऐसी कौनसी योजना आपने बनाई है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें बच्चों का और एरिया का सबका सवाल मिला दिया।

श्री शेर सिंह : यह योजना जो बनी है इसमें ऐसे ही काम रखे गए हैं जिसमें अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके। यह काम इस ढंग के हैं, लेबर इंटेंसिव काम हैं, इन में रोजगार ज्यादा लोगों को मिलेगा, ऐसे काम हम ले रहे हैं। लेकिन साथ-साथ यह भी ध्यान रखा है कि काम करने के बाद कोई एसेट्स भी क्रियेट होने चाहिए। यह नहीं कि जैसे पहले रिलीफ के काम होते थे, मिट्टी डाली, बारिश आई और सारी मिट्टी बह गई। अब हम यह सोच रहे हैं कि सड़क बनानी है तो पक्की बनाएं। कच्चा काम न करवाएं। पक्की सड़क बनवाएं। और भी काम जो हों वह ऐसे हैं कि जिनसे परमानेंट एसेट्स क्रियेट हों साथ-साथ ताकि इन्फ्रा-स्ट्रक्चर बने और उससे और ज्यादा एम्प्लायमेंट क्रियेट हो।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: The extent of employment is really determined by the its income content.

SHRI SHER SINGH: I require notice of this question.

SHRIMATI JYOTSNA CHANDA: The hon. Minister has mentioned the names of almost all States except Assam. I would like to know from him whether Assam has been excluded from this.

SHRI SHER SINGH: No, Assam is very much in the picture. We are taking this scheme to Assam also.

Assessment of Loss of Crop in U. P. due to recent rains and Central Assistance therefore

*1450. SHRI R. S. PANDEY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether *rabi* gains worth hundreds of crores of rupees have been damaged in Uttar Pradesh during the recent rains there;

(b) whether an on-the-spot assessment of this loss has been made by the Central Government and, if so, the main findings thereof; and

(c) the assistance given by the Centre to the State Government to provide relief to the affected farmers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASEHEB P. SHINDE): (a) The U. P. Government has stated that heavy losses to *Rabi* crop have occurred owing to untimely rains in Uttar Pradesh.